ISBN:978-81-974990-9-8

10.कोविड–19का ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रभाव और नवीन अवसर

डॉ. अमित पटेल

सहा. प्राध्यापक,
नेशनल एजुकेशन एण्ड रिसर्च सेंटर,
रायपुर (छ.ग.).

सारांश–

कोरोन का परिचय

कोरोनावायरस वायरसों का एक बड़ा परिवार है जो सामान्य सर्दी–जुखाम से लेकर अधिक गंभीर बीमारियों जैसे मध्य पूर्व श्वसन सिंडोम और गंभीर तीव्र श्वसन सिंडोम का कारण बनता है। एक नए कोरोनावायरसकी पहचान चीन के वुहान में 2019 में हुई थी।यह एक नया कोरोनावायरस है जो इससे पहले कभी मनुष्यों में नहीं पाया गया है।

कोरोनावायरस रोग (COVID-19)SARS-CoV-2 वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। वायरस से संक्रमित ज्यादातर लोगों को हल्की से मध्यम श्वसन संबंधी बीमारी होगी और उन्हें विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं होगी। हालाँकि, कुछ लोग गंभीर रूप से बीमार हो जाएँगे और उन्हें चिकित्सा की आवश्यकता होगी। वृद्ध लोगों और हृदय रोग, मधुमेह, पुरानी श्वसन संबंधी बीमारी या कैंसर जैसी अंतर्निहित चिकित्सा स्थितियों वाले लोगों में गंभीर बीमारी विकसित होने की संभावना अधिक होती है। कोई भी व्यक्ति COVID-19 से बीमार हो सकता है और किसी भी उम्र में गंभीर रूप से बीमार हो सकता है या मर सकता है।

संक्रमण को रोकने और धीमा करने का सबसे अच्छा तरीका बीमारी और वायरस के फैलने के तरीके के बारे में अच्छी जानकारी रखना है। दूसरों से कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखकर, सही ढंग से फिट किया गया मास्क पहनकर और अपने हाथों को बार–बार धोकर या अल्कोहल–आधारित सेनेटाइजर का इस्तेमाल करके खुद को और दूसरों को संक्रमण से बचाएं। अपनी बारी आने पर टीका लगवाएं और स्थानीय दिशा–निर्देशों का पालन करें।वायरस संक्रमित व्यक्ति के मुंह या नाक से छोटे तरल कणों के रूप में फैल सकता है जब वे खांसते, छींकते, बोलते, गाते या सांस लेते हैं। ये कण बड़ी श्वसन बूंदों से लेकर छोटे एरोसोल तक हो सकते हैं। श्वसन शिष्टाचार का पालन करना महत्वपूर्ण है, उदाहरण के लिए मुड़ी हुई कोहनी में खांसना, और यदि आप अस्वस्थ महसूस करते हैं तो ठीक होने तक घर पर रहना और खुद को अलग रखना।

कोरोना वायरस के तीन मुख्य लक्षण हैं.

1. **लगातार खांसी आना**– इस कारण लगातार खांसी हो सकती है यानी आपको एक घंटे या फिर उससे अधिक वक्त तक लगातार खांसी हो सकती है और 24 घंटों के भीतर कम से कम तीन बार इस तरह के दौरे पड़ सकते हैं।
2. **बुखार**– इस वायरस के कारण शरीर का तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है जिस कारण व्यक्ति का शरीर गर्म हो सकता है और उसे ठंडी महसूस हो सकती है।
3. **गंध और स्वाद का पता नहीं चलना**– विशेषज्ञों का कहना है कि बुखार और खांसी के अलावा यह भी वायरस संक्रमण का वह संभावित महत्वपूर्ण लक्षण हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. आपको किसी चीज का स्वाद या गंध नहीं आएगी, या फिर आपको ये नॉर्मल से अलग लगेंगे।

पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के मुताबिक, 85 प्रतिशत कोरोना के मरीजों में इनमें से कम से कम एक लक्षण देखा जाता है. अगर किसी को भी लगता है कि उन्हें कोविड हो सकता है तो उन्हें टेस्ट करवाना चाहिए।

प्रमुख पांच लक्षण हैं :–

1. बहती नाक
2. सिरदर्द
3. थकान (हल्की या बहुत ज्यादा)
4. छींक आना
5. गले में खराश

अगर आपको लगता है कि आपको कोविड हो सकता है, तो आपको तुरंत जांच करा लेनी चाहिए. कुछ लोग भले ही खुद ज्यादा बीमार महसूस ना करें, लेकिन वो दूसरों को खतरे में जरूर डाल सकते हैं।

कोरोना के नए ओमिक्रॉम वेरिएंट का पता सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका की डॉक्टर एंजेलिककोएत्जी ने लगाया था । उन्होंने बीबीसी को बताया कि अभी तक तक वहाँ जिन लोगों में ये वेरिएंट मिला है उनमें कोविड के बहुत मामूली लक्षण नजर आए हैं।

उन्होंने कहा, कि अधिकतर मरीज बदन में दर्द और बहुत ज्यादा थकावट की शिकायत कर रहे हैं, और मैं ये बात युवाओं के बारे में कर रही हूँ. मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो अस्पताल जाकर भर्ती हो गए।

ग्रामीणअर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन मेंCOVID -19का प्रभाव :–

मानव–जीवन के लिए कोरोना वायरस (**COVID -19**) के खतरे से संघर्ष की पीड़ा से गुजर रहा था। लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। इससे निपटने और करोड़ों भारतीयों के स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरे को कम करने के लिए किए गए आपातकालीन उपायों के कारण, अर्थव्यवस्था को एक बड़ा और पूरी तरह अप्रत्याशित झटका लगा था।

औद्योगिक गतिविधियों और शहरी व्यवसाय की गतिविधियों के रुक जाने के कारण, सम्पूर्ण आर्थिक–विकास को बड़े पैमाने पर झटका लगा है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन को किस हद (**COVID -19**) तक प्रभावित करेगा?

ग्रामीण जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में सोचना बहुत आसान है। हालांकि उपलब्ध सार्वजानिक सूचनाओं से इस बात की कोई जानकारी नहीं मिलती, कि ऐसे कितने लोग भारत के ग्रामीण क्षेत्रों मेंऐसा प्रतीत होता है जैसे कि यह बीमारी काफी हद तक मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, आदि जैसे शहरों तक सीमित रही थी।

कुछ शर्तें :–

यहां यह कहना जरूरी है कि इसकी कुछ शर्त हैं। पहली शर्त जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है, वह यह कि भारत में केवल उन लोगों का परीक्षण हुआ है जिनमें बीमारी के लक्षण थे और उन्होंने हाल में विदेश यात्रा की थी, इसलिए समुदाय में इसके फैल जाने के बारे में (यदि ऐसा हुआ है तो) कोई जानकारी नहीं है।

दूसरी शर्त यह है कि बहुत से लोग, जानबूझकर, शरीर का तापमान कम करने के तरीके अपनाकर, प्रवेश–द्वार पर परीक्षण कराने और अलग–थलग (क्वारंटीन) होने से बच निकले। और तीसरी, जिसका बहुत प्रचार भी हुआ है, "लापता" यात्रियों से सम्बंधित है।

एक पक्ष जो मजबूती से रखा जा सकता है कि वे लोग, जो उनके यात्रा दस्तावेजों की तारीख–अनुसार ब्यौरे के आधार पर, जानकारी के अभाव में "लापता" हो गए थे, ग्रामीण क्षेत्रों में, मान लीजिये पंजाब या कहीं और चले गए हैं।

हालाँकि यह कोरी अटकलबाजी हो सकती है। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है, प्रभावित लोगों का बड़ा हिस्सा प्रायः शहरी हैद्य इसमें केरल का कासरगोड संभवतः एक अपवाद हो सकता है, जहाँ वैसे भी शहर और गावों के बीच निरंतरता है।

लौटते मजदूर की स्थिति :–

महाराष्ट्र में मीडिया रिपोर्टों और आसपास की जानकारी से पता चलता है कि लॉकडाउन से पहले, कुलियों, घरेलू कामगरों, आदि सहित, अनियमित या दिहाड़ीदार मजदूर के रूप में काम करने वाले, बड़ी संख्या में लोग महाराष्ट्र के अपने गांवों में लौट आए हैं।

यहां तक कि लॉकडाउन से ठीक पहले, मीडिया उन लोगों की भारी भीड़ की तस्वीरों से भरा हुआ था, जो पूर्व में और आगे जाने वाली ट्रेन या बसें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मुद्दा यह है कि इन लौटने वालों में कुछ इस वायरस को अपने साथ ले आए हो सकते हैं।यदि इन वापिस आने वाले "लापता" एन.आर.आई. या शहरी मजदूरों के बीच, वायरस को साथ ले जाने वाले लोग हुए, तो यह रोग ग्रामीण भारत में भी फैल सकता है।

क्योंकि ग्रामीण भारत में चिकित्सा सामान और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव है, इसलिए यह एक बड़ी समस्या बन सकती है, हालांकि 'सामाजिक–दूरी' (सोशल डिस्टैन्सिंग) की समस्या वहां उतनी नहीं होगी जितनी यह शहरी झुग्गी–झोंपड़ियों में है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था :–

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव शायद थोड़े समय बाद होगा। ग्रामीण लोगों पर शायद इसका तुरंत प्रभाव उतना न हो, जितना शहरी क्षेत्रों के अनियमित और दिहाड़ीदार मजदूरों पर होगा।

इसका कारण यह है, कि ग्रामीण लोगों की आय, किसी एक दिन के काम से ज्यादा उनकी फसल के हालात पर निर्भर करती है। क्योंकि उनमें बहुत से लोग आवश्यक वस्तुओं का भंडार रखते हैं, और छोटी वस्तुएं आमतौर पर स्थानीय बाजारों ('हाट') से खरीद लेते हैं।

कानून लागू करने वाली प्रवर्तन एजेंसियों पर काम के भारी बोझ और अभी तक किसी भी संक्रमण की जानकारी न होने के कारण, यह एक अटकल का विषय है कि हाट सहित, गांवों की नियमित गतिविधियां जारी रहेंगी या नहीं।

सरकार यह घोषणा करती रही है कि लॉकडाउन के बावजूद, बागवानी–उत्पाद और दूध की आपूर्ति को बनाए रखा जाएगा। यदि वास्तव में ऐसा हुआ, तो गांवों और शहरों के बीच थोड़े–बहुत नुकसान, जिसकी भरपाई संभव होगी, के साथ आर्थिक आदान–प्रदान चलता रहना चाहिए।

कोरोना के प्रकोप के नकारात्मक परिणाम ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरे क्रम के प्रभाव छोड़ेंगे। जैसे–जैसे शहरी व्यावसायिक गतिविधियां खत्म होंगी, वैसे–वैसे आमदनी और खरीद–शक्ति कमजोर होगी।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, कि प्रवासी मजदूरों के रूप में शहरों में काम करने वाले परिवारों की आय पर आने वाले कम से कम दो महीनों के लिए चोट पहुंची है या पहुंचेगी।

प्रवासी लोग प्रभावित :–

उत्तराखंड, असम, दक्षिण राजस्थान, उत्तर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी ओडिशा, तेलंगाना, रायलसीमा, खंडेश और मराठवाड़ा प्रमुख क्षेत्र हैं, जहाँ से प्रवासी मजदूर आते हैं।

इन में से कई क्षेत्रों में, ग्रामीण परिवारों का पारिवारिक अस्तित्व और अर्थव्यवस्था, काफी हद तक प्रवासी प्रवासी मजदूर की आय पर निर्भर करते हैं। (**COVID -19**) प्रकोप उस आय की जड़ पर चोट कर रहा है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि होली का त्योहार वह समय है, जब प्रवासी मजदूर पश्चिमी, मध्य और उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में अपने घर लौटते हैं।

शहरों से होने वाली उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा त्योहारों पर खर्च होता है। उनके होली मनाकर काम पर लौटने के एक पखवाड़े के भीतर ही यह लॉकडाउन लागू हो गया। इस प्रकार, इन परिवारों की सहने की सीमित क्षमता समाप्त होते ही वहां ग्रामीण संकट दिखाई पड़ेगा।

आर्थिक मंदी :–

अर्थशास्त्री (**COVID -19**) के कारण आर्थिक मंदी की भविष्यवाणी कर रहे हैं। यदि यह प्रलय–वाणी सच हो गई, तो शहरी क्षेत्रों में श्रम को खपाने के अपने मौजूदा स्तर तक पहुंचने में समय लेगा।क्या इस मंदी का प्रभाव पड़ेगा और पड़ेगा तो किस हद तक? यह एक ओर वैश्विक आर्थिक रुझानों परऔर दूसरी ओर भारत सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले आर्थिक प्रोत्साहन सम्बन्धी सुधारों के आकार पर निर्भर करेगा।

संक्षेप में, ग्रामीण भारत में जीवन और स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव, महत्वपूर्ण रूप से कोरोना वायरस से ग्रस्त लोगों की संख्या पर निर्भर करेगा, जो बिना पकड़ में आए ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच गए हैंद्य लेकिन यदि ऐसा हुआ है, तो उसके प्रभाव का पता लगाना धीमा और नियंत्रण करना बेहद मुश्किल होगा।

COVID -19प्रकोप के आर्थिक प्रभाव नकारात्मक दिखाई देंगे, जिससे ग्रामीण परिवारों को मुख्य रूप से प्रवास में मजदूरी से होने वाली आय के नुकसान से चोट पहुंचेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गाँधी नरेगा के बड़े पैमाने पर विस्तार के द्वारा कम से कम आंशिक रूप से दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। हम आशा करते हैं कि सरकारें इस दिशा में कदम उठाएंगी।

बेरोजगारी दर कोविड–पूर्व अवधि की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक बनी हुई है

कोविड–19के प्रसार को रोकने के लिए मार्च के अंत से मई 2020 तक देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन के दौरान लोगों की आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से जुड़ी गतिविधियों को छोड़कर आर्थिक गतिविधियों पर काफी हद तक रोक लगा दी गई थी। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर बढ़ गई थी। बेरोजगारी दर श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत को संदर्भित करती है। श्रम बल में वे लोग शामिल हैं जो या तो कार्यरत हैं या बेरोजगार हैं लेकिन काम की तलाश में हैं। बाद के महीनों के दौरान लॉकडाउन प्रतिबंधों में धीरे–धीरे ढील दी गई। आकृति 1 वर्तमान साप्ताहिक गतिविधि स्थिति के अनुसार सभी आयु समूहों में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर (आंकड़ेः में)

श्रम बल भागीदारी :–

श्रम बल में आने और बाहर जाने वाले व्यक्ति भी बेरोजगारी दर को प्रभावित कर सकते हैं। किसी निश्चित समय पर, ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो कानूनी कार्य करने की आयु से कम हों या विभिन्न सामाजिक–आर्थिक कारणों से श्रम बल से बाहर हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, शिक्षा हासिल करने के लिए। साथ ही, ऐसे हतोत्साहित कर्मचारी भी हो सकते हैं, जो रोजगार पाने के इच्छुक और सक्षम होते हुए भी काम की तलाश करना बंद कर देते हैं।

श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम :–

श्रम संबंधी स्थायी समिति ने अगस्त 2021 में जारी अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि भारत में श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र से हैं। इन श्रमिकों में शामिल हैं प्रवासी श्रमिक, ठेका मजदूर, निर्माण श्रमिक, और रेहड़ी–पटरी वाले।

समिति ने पाया कि ये श्रमिक मौसमी रोजगार और असंगठित क्षेत्रों में नियोक्ता–कर्मचारी संबंधों की कमी के कारण महामारी से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। ?

समिति ने केंद्र और राज्य सरकारों को सुझाव दिया कि वे

1. उद्यमशीलता के अवसरों को प्रोत्साहित करें।
2. पारंपरिक विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करें और औद्योगिक क्लस्टर विकसित करें।
3. सामाजिकसुरक्षा उपायों को मजबूत करें।
4. अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों का डेटाबेस बनाए रखें।
5. व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा दें।

इसने श्रमिकों का समर्थन करने और कोविड–19 महामारी (शहरी क्षेत्रों पर लागू) द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और खतरों का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों पर ध्यान दिया।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पी.एम.जी.के.वाई.) के तहत केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ता के हिस्से का 12 प्रतिशत और कर्मचारी के हिस्से का 12 प्रतिशत योगदान दिया। मार्च और अगस्त 2020के बीच 2-63 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 38.85 लाख पात्र कर्मचारियों के ई.पी.एफ. खातों में कुल 2,567 करोड़ रुपये जमा किए गए।

अक्टूबर 2020से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य नियोक्ताओं को नए रोजगार के सृजन के साथ–साथ सामाजिक सुरक्षा लाभ और कोविड–19 महामारी के दौरान रोजगार के नुकसान की बहाली के लिए प्रोत्साहित करना था। इसके अलावा, नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के वैधानिक भविष्य निधि अंशदान को तीन महीने के लिए EPF संगठन द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए मौजूदा 12 प्रतिशत से घटाकर 10ः कर दिया गया था। 30जून, 2021 तक, ABRY के तहत लगभग 22 लाख लाभार्थियों को 950 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (जुलाई 2018 में शुरू) के तहत बेरोजगारी लाभ को COVID–19 के कारण रोजगार खो चुके बीमित श्रमिकों के लिए औसत कमाई के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया था।

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना के तहत केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये तक की शुरुआती कार्यशील पूंजी मुहैया कराई है। 28 जून, 2021 तक 25 लाख ऋण आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं और 21.57 लाख लाभार्थियों को 2,130 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।

केंद्र और राज्य सरकारों ने आर्थिक गतिविधि को बनाए रखने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण पर खर्च बढ़ाने और व्यवसायों के लिए सस्ते ऋण तक पहुंच को सक्षम करने जैसे कई अन्य उपाय भी किए हैं।

संदर्भ ग्रंथ :–

1. https://rural.nic.in/about-us/about-ministry
2. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx
3. https://scroll.in/article/ruralemployment
4. http://www.ncap.res.in/agri_lock
5. https://economictimes.indiatimes.com/news/economy
6. पत्र एवं पत्रिकाएं
7. समाचार पत्र